



EPCH
हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्
Export Promotion Council for Handicrafts

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्
**EXPORT PROMOTION
COUNCIL FOR HANDICRAFTS**

EPCH HOUSE Pocket 6 & 7 Sector 'C', LSC, Vasant Kunj, New Delhi-110070
Tel: +91-11-26135256 Fax: +91-11-26135518 & 19 Email: mails@epch.com | www.epch.in

CIN U20299DL1955NPLO23253
GST NO: 07AAACE1747M1ZJ

प्रेस विज्ञप्ति

**भारतीय लकड़ी हस्तशिल्प निर्यात को सुरक्षित रखने के लिए ईपीसीएच ने यूरोपियन यूनियन डीफॉरेस्टेशन
रेग्युलेशन (ईयूडीआर) पर सरकारी हस्तक्षेप की मांग की**

व्यापार ने शीघ्र समाधान के लिए प्रतिनिधित्व में तेजी लाई

दिल्ली/एनसीआर, 21 अगस्त 2025 – हस्तशिल्प निर्यातकों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् (ईपीसीएच) के उपाध्यक्ष श्री सागर मेहता और ईपीसीएच के महानिदेशक की भूमिका में मुख्य संरक्षक और आईईएमएल के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार; ईपीसीएच के नेतृत्व में भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह और माननीय

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस बैठक में यूरोपियन यूनियन डीफॉरेस्टेशन रेग्युलेशन (ईयूडीआर) के अनुपालन में भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई।

बैठक में ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री आर. के. वर्मा तथा जोधपुर के प्रमुख सदस्य निर्यातक श्री मनोज बोथरा, श्री राजेंद्र बंसल, श्री जे. पी. जैन, श्री आशीष मेहता, श्री गौरव जैन, श्री मनीष पुरोहित और सहारनपुर के प्रमुख सदस्य निर्यातक श्री परमिंदर सिंह भी उपस्थित रहे, ईपीसीएच के अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक श्री राजेश रावत ने जानकारी दी।

प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों से भी मुलाकात की।

ईयूडीआर के प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉ. नीरज खन्ना ने कहा, "हम यूरोपीय संघ की वनों की कटाई के खिलाफ उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं, लेकिन ईयूडीआर के अनुपालन की आवश्यकताएं हमारे लकड़ी हस्तशिल्प निर्यातकों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं। हमारे उत्पाद मुख्यतः आम, बबूल और शीशम की लकड़ी से बनाए जाते हैं, जो कृषि वानिकी से प्राप्त होते हैं और प्राकृतिक वनों की कटाई में योगदान नहीं करते।"

उन्होंने आगे कहा, "यदि इन नियमों को स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना लागू किया गया, तो इससे उत्पादन में गिरावट, ऑर्डर रद्द होने और कारीगरों व उनके आश्रितों में व्यापक बेरोजगारी हो सकती है।"

नीतिगत समर्थन पर प्रकाश डालते हुए डॉ. राकेश कुमार ने कहा, "ग्रामीण, शहरी और कस्बाई भारत के लाखों कारीगरों के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र आर्थिक रीढ़ के समान है। ईयूडीआर लकड़ी के निर्यातकों पर समान दायित्व लागू करता है, जो भारत

जैसे देशों की विशिष्ट परिस्थितियों की अनदेखी करता है। सरकार के हस्तक्षेप के बिना, ईयूडीआर के प्रावधानों का अनुपालन करना हमारे निर्यातकों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है।”

उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से आम, बबूल और शीशम की लकड़ी के लिए छूट की मांग करने और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से कटाई के समय भू-स्थान डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने की अपील की, जिससे निर्यातकों को वन-कटाई मुक्त सप्लाई चेन स्थापित करने में मदद मिले।

श्री सागर मेहता ने कहा, “यूरोपीय संघ के वनों की कटाई नियम लकड़ी हस्तशिल्प निर्यातकों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) और कारीगर आधारित उद्यमों के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। हम सतत और जिम्मेदार व्यापार का समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की विशिष्ट प्रकृति को समझना आवश्यक है। हम सरकार और उद्योग के सहयोग से एक व्यावहारिक अनुपालन ढांचा विकसित करने की मांग करते हैं।”

श्री आर. के. वर्मा ने कहा, “ईपीसीएच हमेशा वैश्विक स्थिरता ढांचे के साथ अपने कदम मिलाकर चलने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इसका उदाहरण है ‘वृक्ष’ (वीआरआईकेएस एच- टिंबर लीगलिटी एसेसमेंट एंड वेरिफिकेशन स्कीम), जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली है और भारतीय हस्तशिल्प सेक्टर इसका अनुपालन करता है। लेकिन जिओ-रेफरेंस (भू-संदर्भित) ट्रेसबिलिटी प्रणाली के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए नीति समर्थन, वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। यह सामूहिक दृष्टिकोण प्रावधान अनुपालन को सुनिश्चित करेगा और भारतीय निर्यात प्रतिस्पर्धा को सुरक्षित रखेगा।”

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) दुनिया भर के विभिन्न देशों में भारतीय हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने और उच्च गुणवत्ता वाले हस्तशिल्प उत्पादों और सेवाओं के एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में विदेशों में भारत की छवि और होम, लाइफस्टाइल, टेक्स्टाइल, फर्नीचर और फैशन जूलरी एंड एक्सेसरीज प्रॉडक्ट के उत्पादन में लगे क्राफ्ट क्लस्टर के लाखों कारीगरों और शिल्पकारों के प्रतिभाशाली हाथों के जादू की ब्रांड इमेज बनाने के लिए जिम्मेदार एक नोडल संस्थान है। इस अवसर पर ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री आर. के. वर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हस्तशिल्प का कुल निर्यात 33,123 करोड़ रुपये (3,918 मिलियन डॉलर) रहा। इसके साथ ही वर्ष 2024-25 के दौरान लकड़ी आधारित हस्तशिल्प का कुल निर्यात 8524.74 करोड़ रुपए (1008.04 मिलियन डॉलर) रहा जो रुपये के लिहाज से 6% और डॉलर के लिहाज से 3.84% की वृद्धि दर्ज हुई और अकेले यूरोपीय संघ को निर्यात ₹2,591.29 करोड़ (306.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर), ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री आर. के. वर्मा ने भी बताया।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

श्री आर. के. वर्मा, कार्यकारी निदेशक ईपीसीएच;

+91-9810697868



EPCH
हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्
Export Promotion Council for Handicrafts

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्
**EXPORT PROMOTION
COUNCIL FOR HANDICRAFTS**

EPCH HOUSE Pocket 6 & 7 Sector 'C', LSC, Vasant Kunj, New Delhi-110070
Tel: +91-11-26135256 Fax: +91-11-26135518 & 19 Email: mails@epch.com | www.epch.in

CIN U20299DL1955NPLO23253
GST NO: 07AAACE1747M1ZJ

PRESS RELEASE

EPCH Urges Government Intervention on European Union Deforestation Regulations (EUDR) to Safeguard Indian Wooden Handicrafts Exports

Trade Speeds up representation for Early Solution

Delhi/NCR, 21st August 2025 – A High level delegation of handicrafts exporters led by Shri Sagar Mehta, Vice Chairman, EPCH and Dr. Rakesh Kumar, Director General in the role of Chief Mentor EPCH and Chairman – IEML met Shri Giriraj Singh, Hon'ble Union Minister of Textiles, Govt. of India; Shri Gajendra Singh Shekhawat, Hon'ble Union Minister of Tourism and Culture, Govt. of India to discuss and request the Govt. of India to intervene in the compliance of European Union Deforestation Regulations (EUDR).

The meetings also saw presence of Shri R. K. Verma, Executive Director, EPCH and Shri Manoj Bothra, Shri Rajendra Bansal, Shri J. P. Jain, Shri Ashish Mehta, prominent member exporters from Jodhpur, Shri Gaurav Jain, Shri Manish Purohit and Shri Parminder Singh, prominent member exporters from Saharanpur were present informed Shri Rajesh Rawat, Addl. Executive Director -EPCH.

The delegation also met high level officials to discuss the matter in detail.

Concerning the impact of EUDR, Dr. Neeraj Khanna, Chairman-EPCH, said “While we appreciate the EU’s commitment to combating deforestation, but the EUDR compliance requirements could severely impact our wooden handicrafts exporters. Our wooden handicrafts are primarily made from Mango, Acacia and Sheesham wood which are sourced largely from agroforestry. These species are grown outside natural forests and do not contribute to deforestation.”

“We believe that such stringent compliance requirements, if implemented without contextual adjustments, could lead to significant disruptions. Many artisans and MSME exporters may lose access to EU markets, resulting in reduced production, cancelled orders and widespread unemployment among artisans and their dependents.” Dr. Khanna further added.

Highlighting policy level engagement and support, Dr. Rakesh Kumar, Director General in the role of Chief Mentor EPCH and Chairman – IEML shared that “The handicrafts sector is the economic backbone for millions of artisans in rural and semi-urban India. Despite the sustainable nature of sourcing, EUDR places uniform obligations on all timber exporters, disregarding contextual differences in countries like India. Without government intervention, compliance with EUDR could become prohibitively complex for our exporters. We need a collective approach that combines regulatory support and engagement with the EU.

He further urged Ministry of Commerce & Industry to engage with the EU for seeking exemptions for Mango, Acacia, and Sheesham wood and Ministry of Environment, Forest & Climate Change and Ministry of Agriculture & Farmers Welfare to issue directives to field formations for providing geo-location data at the time of harvesting, enabling exporters to establish a deforestation-free chain of custody.”

Shri Sagar Mehta, Vice Chairman – EPCH said that “The European Union’s deforestation regulations present a critical challenge for wooden handicraft exporters, particularly MSMEs and artisan-based enterprises. While we fully support sustainable and responsible trade, it is essential to recognize the unique nature of our wooden handicrafts sector, which relies on agroforestry and does not contribute to deforestation. We request a collaborative approach involving government bodies, industry stakeholders to develop a pragmatic compliance framework that protects our artisans while meeting global sustainability goal”.

Shri. R. K. Verma, Executive Director, EPCH said “EPCH has always been committed towards aligning with global sustainability frameworks through initiatives like “Vriksh” Timber Legality Assessment and Verification Scheme, an internationally recognized system that assures the legality and sustainability of wood sourcing. However, large-scale implementation of geo-referenced traceability systems requires policy support, funding and international engagement. This collective approach will ensure compliance while safeguarding India’s export competitiveness.”

Export Promotion Council for Handicrafts is a nodal agency for promotion of exports of handicrafts from the Country and create brand image of magic of the gifted hands of millions of craftspersons engaged in production of home, lifestyle, textiles, furniture and fashion jewellery & accessories products in different craft clusters of the Country. The overall Handicrafts exports during the year 2024-25 was Rs. 33,123 Crores (US \$ 3,918 Million) and the exports of wooden Handicrafts during the year 2024-25 was 8524.74 crores (US\$ 1008.04 million) registering a growth of 6% in rupee term and 3.84% in dollar term with exports to European Union alone stood at ₹2,591.29 crore (USD 306.40 million) informed by Shri R. K. Verma, Executive Director, EPCH.

For more information please contact:

Shri. R. K. Verma, Executive Director, EPCH
+91-9810679868

Encl: Hindi, English version with photos





Photo 1, 2, 3 & 4: A High level delegation of handicrafts exporters led by Shri Sagar Mehta, Vice Chairman, EPCH and Dr. Rakesh Kumar, Director General in the role of Chief Mentor EPCH and Chairman – IEML met Shri Giriraj Singh, Hon'ble Union Minister of Textiles, Govt. of India and Shri Gajendra Singh Shekhawat, Hon'ble Union Minister of Tourism and Culture, Govt. of India. The meetings also saw presence of Shri R. K. Verma, Executive Director, EPCH; Shri Rajesh Rawat, Addl. Executive Director -EPCH and Shri Manoj Bothra, Shri Rajendra Bansal, Shri J. P. Jain, Shri Ashish Mehta, Shri Parminder Singh, Shri Gaurav Jain and Shri Manish Purohit prominent member exporters were present.